उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रान्त ने ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग पर किया मंथन

- *प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन बढ़ाने पर जापानी प्रतिनिधिमंडल के लिए ऊर्जा विभाग से हुई महत्वपूर्ण बैठक*

लखनऊ, 14 फरवरी, 2025:

ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन तथा आपसी समन्वय बढ़ाने के साथ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के विकास के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से जापान के यामानाशी प्रान्त से आए प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के बीच परिचर्चा का आयोजन लखनऊ के एक होटल में किया गया।

यामानाशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रान्त के माननीय उप-राज्यपाल, श्री कोऊ ओसाडा (Ko Osada) ने किया, उनके साथ यामानाशी प्रान्त सरकार के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति प्रभाग के निदेशक श्री कोइची फुरुया (Koichi Furuya) और यामानाशी प्रान्त सरकार के सलाहकार श्री नीरेंद्र उपाध्याय भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने चर्चा की अध्यक्षता की और ग्रीन हाइड्रोजन तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में जापानी राज्य से तकनीकी सहयोग पर मंथन किया।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर, 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रान्त (जापान) के बीच ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। दि. 13 फरवरी, 2025 को समझौते को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से माननीय उप राज्यपाल श्री कोऊ ओसाडा, माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, तकनीकी विकास और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की। मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के तीन मुख्य घटक- उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर ध्यान आकर्षित किया।

प्रमुख सचिव, श्री नरेंद्र भूषण ने प्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों पर प्रकाश डाला, जिसने उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में 'टॉप अचीवर' बनाया, साथ ही यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 की मुख्य विशेषताएं भी बताईं।

यूपीनेडा ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के साथ एक पोर्टल लॉन्च किया, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब तक पोर्टल के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं के लिए 09 प्रस्ताव मिले हैं। कुल मिलाकर, बारह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें: सेंटर-ऑफ-एक्सीलेंस (सीओई) के लिए 06, इनक्यूबेटर के लिए 04 और स्टार्ट-अप के लिए 02 प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही बीएचईएल, एनटीपीसी, आईईटी, इन्वेस्ट यूपी और आईआईटी-दिल्ली की एक विशेषज्ञ समिति इन प्रस्तावों की निगरानी और मूल्यांकन भी कर रही है।

माननीय उप राज्यपाल श्री ओसाडा ने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति राज्य सरकार के सकारात्मक रवैये और ईंधन उत्पादन को सुविधाजनक बनाने में ऊर्जा विभाग की भूमिका पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे ग्रीन हाइड्रोजन के तीन मुख्य क्षेत्रों: भंडारण, उत्पादन और वितरण में काम करने के इच्छुक हैं। चर्चा के दौरान श्री अनुपम शुक्ला, निदेशक-यूपी नेडा, श्री पंकज कुमार, एमडी-यूपीपीसीएल और अन्य अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।